

[श्री श्रीम प्रकाश एवांगो]

यह कह कर ले आया जाता है कि हम तुम्हें मजदूरी दिलायेंगे। तीन तीन रुपये के हिसाब से उनको मजदूरी एववांस दे दी जाती है और इस प्रकार से एक वृद्धक रच कर उनको यहाँ ले आया जाता है। ठेकेदार भी मजदूरों की मजदूरी में से पैसा लेता है और जो भट्टा मालिक होता है वह क्या करता है कि उनको घाटे के रूप में और चावल के रूप में खर्चा दे देता है और अपने हिसाब में सब खर्चा लिख लेता है। आखिर

जब सीजन समाप्त होता है तब हिसाब करता है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि हिसाब निकालने के बाद उनको बना दिया जाता है कि उनकी तरफ और रुपया निकलता है और उनको ननम्वाह देने के बजाय उनके खिलाफ और रुपया निकाल दिया जाता है और रुपया निकालने के बाद यह कह दिया जाता है कि या तो वह रुपया अदा कर दे नहीं तो उनके परिवार के लोगों को नहीं जाने दिया जायेगा और परिवार के लोगों को जबर्दस्ती रखा लिया जाता है। यह इसलिए भी किया जाता है ताकि अगले सीजन में वे लोग काम करने के लिए आये। वहाँ पर रहने का जो मालिक लोग उनका खर्चा करते हैं उस खर्च में और झूठा खर्चा बना कर और जोड़ कर उनके जिम्मे पैसा निकाल दिया जाता है। वे बेचारे अनारुह लोग होते हैं और हिमाब किताब नहीं जानते हैं। कुछ मजदूर उम गुलामी में से निकलने की कोशिश करने हैं तो उनके परिवार वालों को होस्टेजिज्ज के रूप में रख लिया जाता है, जो मालिक है चाहे वहाँ काम न भी हो तो भी उनको रख लेता है। इस प्रकार वे बेचारे जिनकी भर उनके बगल से निकल नहीं पाते हैं। वे राजस्थान आदि हिस्सों में जाते हैं और जो वहाँ मनी लेंडर होता है, धनी लोग होते हैं उन से कर्जा लेकर आते हैं ऊँची दर पर और यहाँ कर्जा चुकाने की कोशिश करने हैं। इस प्रकार से उनके साथ अन्याय हो रहा है। आपने पाच रुपया

मजदूरी देने का कानून बनाया है लेकिन उनको नहीं मिल रही है। यह अन्याय उनके साथ हो रहा है, कोई योजना नहीं है। उनकी तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उनकी यूनियन नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मशीनरी नहीं बनाई गई है जो जांच करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी तरफ आपका ध्यान जाये। इन मजदूरों ने बोट क्लब पर आ कर प्रदर्शन भी किया था, वे वहाँ पड़े रहे, उनके बीबी बच्चे पड़े रहे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन मजदूरों को आप वृद्धक प्रथा से मुक्त करे और वाक्यादा उनको कानून के हिसाब से मजदूरी दिलाए। इसके बारे में कुछ न कुछ व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए।

(iv) HARSHIPE FACED BY TOBACCO GROWERS IN ANDHRA PRADESH

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) Sir, under rule 377 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Lok Sabha, I want to raise the following urgent issue and request that the Minister concerned may make a statement on that.

The tobacco growers in Andhra Pradesh, particularly in areas like Guntur, Krishna, Nellore and Khammam districts where Virginia tobacco is grown, are suffering a lot since the tobacco traders in general, and the monopoly traders like ILTD etc in particular, are refusing to purchase the stock. They are compelling the growers to sell at a distress price, which means only 50 per cent of the normal price. The growers who are already faced with a terrible loss due to the cyclone, are now put to further ruin by the traders. They refuse to purchase tobacco at the indicated prices fixed by the Tobacco Board since they are not statutory. They also refuse to limit grading only to eight categories, and want to grade as they like. Since the Government does not provide funds to the Tobacco Board to purchase stocks at a fair price in season and dispose it of later, the gro-

wer is not protected at all. Taking advantage of this, the traders are forcing the growers to sell at distress prices.

This year, the traders have delayed the opening of the market. Even now, though they have formally opened, they are offering low prices. The price for a particular grade which used to sell at Rs 1000 is now Rs 500. So, the Government has to take steps immediately to protect the growers by taking their stocks with advance payment and compelling the traders to purchase the stocks at fair prices and if they refuse, their licences should be cancelled.

So many telegrams and messages have come. It is a very serious situation. I appeal to the Government to take note of it and to the rescue of the growers immediately.

(v) Reported Refusal by sugar Mills to buy sugarcane at officially fixed rate.

श्री बसन्त साठे (अकोला) : अध्यक्ष जी, मैं उप सदन का ध्यान सरकार का ध्यान एक वहुता हो सम्भार विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। परम्परा में यहाँ गार्जगवाद गया था और वहाँ के लोग धान उस इलाके के लोग इनके चिन्तित हैं। हमने वे जो दाम एक-एक घट गये हैं। एक बहून बड़ी मिल, मरुवनी शुगर मिल बन्द हो गई है। अम मन्त्री जी ध्यान दें, जो निधार्गिन दाम ये 13 रु० 50 पैसे कानून से तय हुए, वह भी नहीं देने हैं। तो आप कानून में उनको कम्पैल कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी मिल को टेक ओवर करने की भी आपने पाम ताकत है। लेकिन मिल मालिक कहते हैं कि जनता सरकार तो हमारी सरकार है। हमने इनको लाखों रुपये दिये हैं यह हमने खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकते हैं। 13 रु० 50 पैसे दाम देने की वह तैयार नहीं है। खड़ा का खड़ा गन्ना, ईश सूख रही है। बहुत परेशान है

किसान। आज बाज़ू के किसान जो जय जयकार मनाने के लिये, किसान दिवस मनाने के लिये 23 अक्टूबर को यहाँ आयें थे, आज वह किसान नारा लगा रहे हैं, "अकोला नौ, गन्ना छ, और बोलेगा चरण सिंह की जय। पाती सात और गन्ना छै। जय जनता की बोलिये गन्ना मुक्त तोलिये। इन्दिरा जी का नारा था तो गन्ना बिका 18 था। इन्दिरा गांधी आयेंगी, फिर वही भाव लायेंगी।" यह पच्चे में छपा है। यह चौधरी चरण सिंह के काले कारनामे का नोटिस होगा तो मुझे नहीं मालूम। 70 लाख टन गन्ना पैदा हुआ। अब कहा जा रहा है किसान को कि क्यों गन्ना ज्यादा पैदा किया? भूगतो। तो ज्यादा गन्ना पैदा करना यह भी सुनाह हो गया। ज्यादा गन्ना पैदा करो तो ज्यादा अक्कर पैदा होगी और उसको विदेशों में भेज कर विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। तो किसान ने अच्छा किया या बुरा किया? क्या सरकार की अक्ल का दिवाला पिट गया जो किसान को यह कहा जाय कि क्यों ज्यादा पैदा किया? मरा। ता यह बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही है। आज वह क्या कहते हैं—अच्छा भइया हमने ज्यादा किया ना माँ छोड़ो, पिछले साल मिलों ने जितना लिया था 65 लाख टन, उतना तो लेगे।

इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर दोनों मिल कर इस मिल को तो कम-स-बस कच्चे में ले कि खाली पैसा हो लेगे? मिल ले। आप किसानों को दाम दिलाइये, नहीं तो यह किसान दिवस मनाने वाले किसान यहाँ आगे दूसरा दिवस मनाने के लिये। सोचिये,

I hope, this Government will take note of this. Otherwise, tomorrow you must not blame me that 'you did not bring this to the notice of the Government'.